भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3813
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: उच्च मूल्य वाली फसलें और नमो ड्रोन दीदी योजना

3813. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) काजू, कोको और मेवों जैसी भारतीय उच्च मूल्य वाली कृषि फसलों की उत्पादकता और पैदावार को बढ़ाने तथा उन्हें वैश्विक प्रीमियम ब्रांडों में बदलने के लिए क्या नीतिगत कार्यनीतियां तैयार की गई हैं;

(ख) नमो ड्रोनों दीदी योजना की तैनाती में कितनी प्रगति हुई है और देश के राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सफलतापूर्वक वितरित किए गए कृषि ड्रोन की संख्या कितनी है; और

(ग) तमिलनाडु में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रशिक्षित महिला स्वयं सहायता समूहों की सटीक संख्या कितनी है तथा जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु श्रीअन्न मिशन का विस्तार करने हेतु कितनी निधि प्रदान की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य काजू, कोको और मेवे जैसी उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत, नर्सरी की स्थापना एवं उन्नयन, सामान्य एवं उच्च घनत्व के साथ क्षेत्रफल विस्तार, जीर्ण बागों का पुनरुद्धार, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) और एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम) को अपनाना तथा फसलोपरांत प्रबंधन, जिसमें प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांडिंग शामिल हैं, जैसे प्रमुख कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र के विस्तार को प्रोत्साहित करने, उत्पादकता में सुधार करने और उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2025 में एमआईडीएच के प्रचालन दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया था, जिसमें बेहतर लागत मानदंड और काजू, कोको और मेवों सहित बागवानी फसलों के लिए अधिक सहयोग शामिल था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - काजू अनुसंधान निदेशालय (आईसीएआर-डीसीआर), पुत्तूर उन्नत किस्मों, कीट एवं रोग

प्रबंधन और उच्च घनत्व रोपण के माध्यम से काजू उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास के क्षेत्र में कार्यरत है। आईसीएआर-डीसीआर, पुत्तूर द्वारा विकसित कुछ किस्में नेत्रा गंगा, नेत्रा जंबो-1, नेत्रा उभया और नेत्रा जंबो-2 हैं। आईसीएआर-केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीपीसीआरआई), कासरगोड किस्मों के विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से कोको की उत्पादकता, गुणवत्ता और उपयोगिता का संवर्धन करता है। इस संस्थान द्वारा विकसित कुछ किस्में इस प्रकार हैं: कोकोआ संकर (वीटीएलसीएच 1 से 5) और सेलेक्शंस (वीटीएलसीएस 1 और 2)। आईसीएआर-केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (आईसीएआर-सीआईटीएच) गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, उन्नत प्रौद्योगिकियों और मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से शीतोष्ण क्षेत्रों में उगने वाले मेवों के जलवायु-अनुकूल और सतत उत्पादन को भी बढ़ावा देता है।

(ख): नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत, चयनित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन वितरित करने के लिए प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) को ड्रोनों का पहला बैच खरीदने का अधिदेश दिया गया था। उर्वरक विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान एसएचजी की ड्रोन दीदियों को 1,094 ड्रोन वितरित किए गए हैं। सभी लाभार्थियों को नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा अधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठनों (आरपीटीओ) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन प्राप्त करने वाले एसएचजी का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): तमिलनाडु राज्य में 44 नमो ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षित किया गया है और सभी 44 प्रशिक्षित लाभार्थियों को ड्रोन वितरित किए जा चुके हैं।

तमिलनाडु मिलेट मिशन राज्य सरकार का मिलेट की खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम है। तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मिलेट विकास गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुकूल परिस्थितियों वाले 26 जिलों को दो विशेष क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। मिशन का उद्देश्य मिलेट के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक, 178.49 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय की तुलना में 164.73 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। मिलेट की खेती को बढ़ावा देने और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों के माध्यम से मिशन से लगभग 10.17 लाख किसानों को लाभ हुआ है।

वर्ष 2026-27 के लिए, तमिलनाडु राज्य के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)-न्यूट्री-सीरियल (श्री अन्न) के तहत 4394.197 लाख रुपये (केंद्रीय हिस्सा + राज्य हिस्सा) की राशि अनुमोदित की गई है।

अनुलग्नक

नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**ड्रोन उपलब्ध कराए गए स्वयं सहायता समूहों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	108
2.	असम	28
3.	बिहार	32
4.	छत्तीसगढ़	15
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	58
7.	हरियाणा	102
8.	हिमाचल प्रदेश	4
9.	जम्मू-कश्मीर	2
10.	झारखंड	15
11	कर्नाटक	145
12.	केरल	51
13.	मध्य प्रदेश	89
14.	महाराष्ट्र	60
15.	ओडिशा	16
16.	पंजाब	57
17.	राजस्थान	40
18	तमिलनाडु	44
19.	तेलंगाना	81
20.	उत्तर प्रदेश	128
21.	उत्तराखंड	3
22.	पश्चिम बंगाल	15
कुल		**1094**

******